

The Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

?That the Bill to establish the Anusandhan National Research Foundation to provide high level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship in the fields of natural sciences including mathematical sciences, engineering and technology, environmental and earth sciences, health and agriculture, and scientific and technological interfaces of humanities and social sciences, to promote, monitor and provide support as required for such research and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.??(Interruptions)

जिन माननीय सदस्यों ने आज हाउस में अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है, वे इस बात पर पछताएंगे कि यह बिल 75 वर्षों के बाद, पहली बार, इस सदन में लाया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि अगले 75 वर्षों में भी इस तरह का कोई बिल आएगा। It is, in a way, history in the making. The choice is left to us whether we make ourselves part of the history or deprive us of this historic opportunity in the history of India's Parliamentary proceedings.

जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले आठ-नौ वर्षों में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक भौगोलिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आज देश-विदेश में भारत का लोहा माना जा रहा है। यह मुख्यतः इस कारण संभव हुआ है कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य पहली बार दुनिया के सामने आया है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हमारे यहां ह्यूमन रिसोर्स की कभी कमी नहीं थी, प्रतिभा की कमी नहीं थी, योग्यता की कमी नहीं थी, मेहनत करने का माइदा कभी कम नहीं था। हमारे युवा वैज्ञानिकों के आंखों में सपने भी थे। आपने साराभाई का वह चित्र देखा होगा कि

जब वे बाइसाइकल के कोरेयर पर अपना लॉचर व्हीकल लेकर जाते थे। शायद, अभाव इस बात का था कि नीति निर्धारित करने वालों के स्तर पर या नेतृत्व में उस प्रकार का सहयोग या सहायता उपलब्ध नहीं था, and for the first time, the hon. Prime Minister Modi-ji has provided an enabling milieu, जिसमें हर प्रकार की क्षमता को अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे आउटलेट मिला और यह इसलिए संभव हुआ कि इन गत नौ वर्षों में प्रधान मंत्री जी ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए और बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ डाला। Many taboos of the past were broken. अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। आज नतीजा यह है कि 150 से अधिक स्टार्टअप्स इसरो में काम कर रहे हैं। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय आरंभ हुई थी, जब तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद्र की धरती पर पैर रखने, आदमी उतारने के स्वप्न देख रहे थे और हम 'चंद्रा मामा दूर के?' गीत गा रहे थे। लेकिन, आज वह स्थिति है कि भले ही अमेरिका का एक मानव, नील आर्मस्ट्रांग, सन् 1969 में चांद्र की धरती पर उतर कर आया है, लेकिन अपने आगे-पीछे अपने आजू-बाजू पानी अथवा जल की उपस्थिति न देख सका। यह हमारा चंद्रयान था, जो जल का चित्र लाया और आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान अपने शोध के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों की प्रतिक्षा करते हैं।

इसी प्रकार क्वांटम मिशन को अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने लॉन्च किया, जिसने हमें विश्व के उन 4-5 देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और जहां दूसरे देश हैं, वहीं हम हैं। पहले यह हुआ करता था कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती, वह 10-15 वर्ष विदेश में लागू रहती, जब वह लोकप्रिय हो जाती तब हम उसे लाते। मैं आपके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण टेलीविजन का रखना चाहूंगा। अमेरिका में 1950 के दशक में भी टेलीविजन चलता था और वहां पर 1960 का राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, जिसमें एक बड़े ही नाटकीय ढंग से, डामैटिक तरीके से रिचर्ड निक्सन को जॉन कैनेडी ने हराया था और वहां का टीवी डिबेट एक टर्निंग पॉइंट था। जबकि हमें तब यह कोई इल्म ही नहीं था, गुमान नहीं था कि टीवी होता क्या है? हमारे यहां टीवी 1970 के दशक में आया और वह भी एक सप्ताह में आधा घंटा चित्रहार आता था। लेकिन, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि with all the confidence at our command that we are moving at the same pace, rather in many ways ahead of other countries. The other countries are looking up to us. इस प्रकार की भौगोलिक भूमिका को सुचारू रूप से निभाने के लिए हमें कुछ उसी तरह के प्रावधान भी करने पड़ेंगे।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान? कुछ एक देशों ने इस प्रकार के प्रतिष्ठान कायम किए हैं। आज हम उन देशों के साथ जुड़कर और उनसे

एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जब 03 जनवरी, 2019 में हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था, तब प्रधान मंत्री जी की ओर से ही यह सुझाव आया था कि क्या इस प्रकार का कोई अनुसंधान प्रतिष्ठान भारत में भी कायम किया जा सकता है। सच पूछिये तो ?जय अनुसंधान? का आह्वान भी उन्होंने ही किया था। उसके उपरांत वर्ष 2019 में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें भी इसका उल्लेख आया था। फिर उसके बाद एक और मील का पत्थर एनईपी, 2020 ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जो शायद बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, न मालूम क्यों इतने साल उस पर किसी ने विचार नहीं किया? हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुराने तकाजे, पुराने मापदण्डों पर आधारित थी, जो हमारे छात्रों, युवाओं को भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार करने में असमर्थ थी। हालांकि, उसका नाम तक ह्यमून रिसोर्स था। वह कोताही भी दुरुस्त हुई। आज उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, because human resource has a different connotation in the corporate world and even in other worlds. वहां से लेकर आज तक उसमें एक्सीडेंटरी का प्रावधान है। आप अपने विषय चुन सकते हैं, आप विषय बदल सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा, स्किल और एट्रिट्यूड के अनुकूल अपना रास्ता तय कर सकते हैं। उसी को जोड़ते हुए, उस प्रतिभा को, उस क्षमता को पूरा अवसर मिले, यह और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि इस प्रकार की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाए। अब प्रमुख तौर पर अगर कहा जाए कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी या इसे शीघ्र लाने की इतनी क्या मजबूरी थी, तो शायद संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, उसमें कुछ एक मिसिंग लिंक थे। उदाहरण के तौर पर हमारी फंडिंग में, हमारे अधिकतर अनुसंधान के केन्द्र और विभाग विश्वविद्यालयों में हैं। लेकिन, यह साइंस इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज़ और दूसरे संस्थानों में भी फैले हुए हैं। हमारे जो फंडिंग के स्रोत थे, जैसे हमारे यहां एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वह स्पर्धा के आधार पर ग्रांट देता था। स्पर्धा के आधार पर आईआईटीज़ जैसे संस्थान लगभग 65 प्रतिशत ग्रांट के हकदार हो जाते एवं मात्र और मात्र 11 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध रहती। बिल के इंट्रोडक्शन के समय किसी ने यह कहा था कि यह बिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि हम राज्यों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनके विश्वविद्यालयों में जो साधन वे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसके माध्यम से वह किए जाएंगे। इसलिए यह कल्पना आई कि एक हाई लेवल थिंक टैंक बनाया जाए, जो कोऑर्डिनेशन करे for the long-term and the short-term research. जो सीडिंग करे, फैसिलिटेट करे कि जहां अच्छा अनुसंधान हो रहा है और जो वैज्ञानिक ढंग से स्वयं भी शोध करें कि किस प्रकार के विषयों पर हमें नवाचार करना है, शोध करना है। किस तरह की कोलैबोरेशन हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे ताकि हमारी भौगोलिक

भूमिका दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाए। इसके साथ ही साथ, ट्रांसलेशनल रिसर्च भी हो। ऐसा अनुसंधान, जो मात्र प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहे और वह समाज के किसी कार्य न आए, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उसका ट्रांसलेशन करके, उसको अनुवादित करके समाज के हित में लाया जाए, चाहे वह विकास के कार्य हों, चाहे वह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य हो, चाहे समाज सुधार के कार्य हों। इसलिए पब्लिक प्राइवेट को-ऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज समय आ गया है कि धीरे-धीरे पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दूरी को समाप्त किया जाए क्योंकि यदि हमें सामूहिक तौर पर विकास करना है, तो इन बंदिशों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। यह संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को भी जोड़ा जा सके, so that we have a healthy synergy of research, academia, industry, start-ups, and entrepreneurship. इसके साथ-साथ, जो फण्डिंग होगी, जैसा कि मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उसकी कोई ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। कई बार उसके उतने आउटकम नहीं रहते हैं, जिसकी अपेक्षा थी। इस संस्था के पास एक्सपेंडिचर को एनालाइज़ करने का भी प्रावधान रहेगा कि कितना देना है, कितना नहीं देना है। इसके साथ-साथ, उसका समय-समय पर सर्वे भी होगा। अभी मैं लम्बी बात नहीं करता हूँ। इसके बाद जब मैं उत्तर दूँगा, तब अगर कुछ आवश्यक रहा, तो बताऊँगा, लेकिन मुख्य तौर इसके प्राशासनिक प्रावधान में दो संस्थाएं रहेंगी- एक गवर्निंग बोर्ड, जिसके एक्स-ऑफिसियो अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होंगे। उसके सदस्यों में शिक्षा मंत्री, विज्ञान मंत्री और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होंगे। इसी प्रकार से, उनके पास यह भी प्रावधान रहेगा कि वे कुछ मेम्बर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा भूमिका देने का प्रयास है। लगभग पाँच सदस्य उद्योग जगत से हो सकते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंसेज से भी सदस्य लिये जा सकते हैं ताकि विज्ञान की खोज में कहीं सोशल एंगल न लुप्त हो जाए। इस गवर्निंग बोर्ड के नीचे कामकाज चलाने के लिए एक्जिक्युटिव काउंसिल रहेगी, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहेंगे। सारे संबंधित सचिव उसके मेम्बर होंगे और इसके पास भी यह अधिकार होगा कि ये बाहर से भी जिन-जिन विशेषज्ञों को उचित समझें, नियुक्त कर सकें। इसका बजट लगभग 50 हजार करोड़ रुपए रखा गया है, जो 5 वर्षों के लिए है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा निर्णय है। विज्ञान को लेकर आज तक 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी थी। इस 50 हजार करोड़ रुपए में से सरकार की ओर से, आरंभिक समय के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च को समाप्त करके इसी में शामिल किया जाएगा, तो उसका बजट 4 हजार करोड़ रुपए इसी में आ जाएगा और 36 हजार करोड़ रुपए अन्य साधनों से प्राप्त किये

जाएंगे । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है । A huge, huge step towards involving private sector. यह 36 हजार करोड़ रुपए प्राइवेट इंडस्ट्रीज से भी आ सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट से भी आ सकते हैं और देश-विदेश से जो सहयोग करना चाहें, उनसे भी आ सकते हैं ताकि उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट भी महसूस हो, इससे मुनाफा भी कमाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से योगदान किया जा सके ।

मुझे लगता है कि इस बिल पर कोई बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे समझने की आवश्यकता थी । अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यहाँ रहते, तो शायद और अच्छा होता, हम भी उनसे कुछ सुझाव लेते । इसी प्रार्थना के साथ, मैं निवेदन करूँगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठामन स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023 के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में इस तरह का कोई विधेयक नहीं आया और न ही अगले 75 वर्षों तक आने की कोई संभावना है । यकीनन, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात का समर्थन करता हूँ । मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि पहली बार भारत में पूरी दुनिया की रिसर्च के साथ और उनसे आगे बढ़ने के लिए इस तरह का बिल लेकर आए हैं, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । जिससे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का काम हो । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।
(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, यह स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है । जब 75 वर्षों के बाद ऐसा बिल आया है, तो मुझे लगता है कि इस पर विस्तार से बोलने की जरूरत है कि आखिर यह बिल किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या काम करेगा?

माननीय मंत्री जी ने इस बिल पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल माननीय प्रधान मंत्री जी की संकल्पना को पूर्ण करता है। खास तौर से, जब दुनिया के किसी भी मुल्क में वे जाते थे, तो देखते थे कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ? आरएंडडी कहते हैं, हर देश के लोग आरएंडडी में लगे हुए हैं, चाहे यूएसए हो, युरोपियन यूनियन हो या चाइना हो। आखिर उनकी भी ताकत बढ़ी है। हमारे देश में क्यों नहीं हम आरएंडडी पर जोर देते थे?

अभी तक शायद कोई भी सरकार इस बात की कल्पना तक नहीं करती थी। जब कोई बात आती थी, चाहे किसी वैक्सीन के लिए बात हो, किसी एंटीबायोटिक की बात हो, किसी मेडिसिन की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो। मान लीजिए, आने वाले दिनों में अगर ग्रीन एनर्जी की भी बात हो, तो हम भारत के लोग अभी तक केवल इस पर निर्भर रहते थे कि अमेरिका में रिसर्च होगा, जापान में रिसर्च होगा, चाइना में रिसर्च होगा या युरोपियन यूनियन में रिसर्च होगा और उस रिसर्च को भारत भी आने वाले कुछ वर्षों के बाद अपनाएगा। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ कि कैसे हम टीवी के युग से लेकर आज के युग में पहुंचे हैं। हम सोचते थे कि हम फिर उसको एडाप्ट करेंगे।

माननीय सभापति जी, मुझे लगता है कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने या दुनिया में जिस तरीके से एक आवश्यकता महसूस हुई और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी तक हम रिसर्च, टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के लिए दुनिया के दूसरे प्रगतिशील मुल्कों पर निर्भर रहते थे कि हम उनसे टेक्नोलॉजी लेकर ?मेक इन इंडिया? का कार्य करेंगे।

मुझे लगता है कि इस बोर्ड के स्थापित होने के बाद दुनिया हम पर निर्भर होगी कि भारत से टेक्नोलॉजी मिलेगी और इससे निश्चित तौर पर दुनिया के लोग आगे आएंगे। इसीलिए, अभी तक स्टक्चर था, कहीं अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग ढंग से रिसर्च हो रहा था। इस बिल ने यह काम एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से किया है।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आखिर इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस बिल का उद्देश्य मैं बताना चाहूंगा। ?अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन? ? यह एक टर्मिनोलॉजी है कि हम अनुसंधान, मतलब, नैशनल रिसर्च फाउंडेशन ? एनआरएफ का गठन करेंगे। लेकिन एनआरएफ के गठन के दौरान उसका जो स्कोप होगा, जो दायरा होगा, जो डोमेन होगा, वह कौन-कौन सा क्षेत्र होगा?

हम इसका गठन ही इसलिए कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक एसईआरबी ? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एक बोर्ड था, जिस बोर्ड का दायरा बहुत लिमिटेड था। फंडिंग की बात भी कही गई कि आईआईटी और आईआईएम वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोसीड कर जाते थे। देश में हायर एजुकेशन के लिए 45,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होंगी। हर जिले में हायर एजुकेशन के जो भी ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, वहां टीचिंग के सिवा रिसर्च वर्क नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी, बताया गया है कि 11 परसेंट आता है, जबकि ज्यादा पैसा आईआईटी और आईआईएम को जाता था। अतः अभी तक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जो सिस्टम था, उसमें यूनिवर्सिटीज को पैसा नहीं मिलता था। उसमें हायर लेवल के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजों को रिसर्च का पैसा नहीं मिलता था। कब तक हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के अनुसार केवल बाबू प्रोड्यूस करते रहें और जो हमारे यहां का ब्रेन है, वह ब्रेन-ड्रेन होकर, रिसर्च के अभाव में अमेरिका चला जाए, सिलिकॉन वैली चला जाए?

मुझे लगता है कि इस बोर्ड को स्थापित करने से सबसे बड़ा काम होगा कि आज अमेरिका के सिलिकॉन वैली या दुनिया में कहीं भी रिसर्च में लगे हुए हमारे आईआईटीज के जो लड़के हैं, अब वे दुनिया में रिसर्च नहीं करेंगे, बल्कि भारत में रिसर्च का बुनियादी ढांचा ऐसा बनेगा कि भारत का यह ब्रेन इसी भारत में उपयोगिता के लिए काम करेगा।

इसीलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। वाकई मैं प्रधान मंत्री जी के उस विज़न को, जो इस बिल के माध्यम से भारत के 135 करोड़ लोगों को मिल रहा है। यह बिल आज के लिए नहीं है, यह सदन गवाह रहा है कि इस सदन में जो भी बिल हम पारित करते हैं, वह वर्तमान संदर्भों के लिए करते हैं, वर्तमान आवश्यकताओं के लिए करते हैं। कहीं किसान के हित में करते हैं, कहीं कोआपरेटिव के क्षेत्र में करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारिता का बिल लेकर आए। फॉरेस्ट के रिजर्वेशन की बात हो, कंजरवेशन की बात हो, वॉटर रिसोर्सेस की बात हो, हर बिल का मकसद वर्तमान होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह बिल केवल वर्तमान के लिए नहीं, बेहतर कल के लिए है, जिस बिल को माननीय मंत्री जी आज लेकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल फ्यूचर के लिए है। मैं कह सकता हूँ कि यह बिल फ्यूचर के लिए क्यों है? आखिर इस बिल में अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात है, आज पूरे स्पेस में हाइड्रोजन है, लेकिन वह हाइड्रोजन स्पेस में किसी के साथ है, उसको निकालकर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो क्या यह बिना आरएंडडी के हो जाएगा? आज अगर दुनिया में पेट्रोलियम के रिजर्व की बात होती है, पूरी दुनिया में एक बहस है कि शायद अगले

50 वर्षों तक दुनिया का रिजर्व खत्म हो जाएगा। दुनिया को चिन्ता हो या न हो, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों में, आज देखिए श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल का क्या भाव है, पाकिस्तान में क्या भाव है, तो जब पेट्रोल और डीजल का रिजर्व आने वाले 50 वर्षों में खत्म हो जाएगा, यूएसए के पास स्टॉक होगा, उसका भी खत्म हो जाएगा, तो कौन सी एनर्जी से हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। कौन सी एनर्जी से हम आने वाले दिनों में इसका विकल्प तय करेंगे? मुझे लगता है कि जब लोगों के सामने क्राइसिस आएगी तब दुनिया सोचेगी, तब वे देश सोचेंगे और भारत में 50 वर्ष के पहले प्रधानमंत्री जी ने आज सोच लिया, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की। Green hydrogen as a source of fuel and a new method to produce hydrogen, इस पर भी हमें रिसर्च करनी है। इसका स्कोप कितना बढ़ रहा है?

हमने फर्टिलाइजर पर बार-बार, हमारे फर्टिलाइजर मंत्री जी अभी बैठे थे, वे कहते हैं कि हमने पिछले 5 वर्षों में, India in the last five years has paid Rs.10 lakh crore towards fertilizer subsidy. अब भारत की पब्लिक के एक्सचेजर का पैसा, 10 लाख करोड़ रुपया, जो भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लग सकता था, प्रधानमंत्री गति शक्ति, जो तमाम बुनियादी विकास के ढांचे थे, उन्होंने उन सारे अंतर-मंत्रालयों को एकसाथ जोड़ा और उन्होंने यह तय किया कि हम उसको एक गति देंगे। चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इन सारी चीजों के लिए किया। जब हम देश के किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आखिर इसका विकल्प अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा होता और इस पर रिसर्च नहीं हुई होती तो आज उस फर्टिलाइजर का एक जिस तरह से विकल्प नैनो यूरिया लेकर आए हैं, जो कि अपने आपमें एक क्रान्ति है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। As part of the plan, about 8.5 million tonnes of urea would be replaced with 170 million bottles. अभी हमारे यहाँ सहकारिता का सम्मेलन हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जेपीएस राठौर जी आए थे। हम कई बोरे यूरिया के खेत में छिड़कते हैं, जो जमीन पर भी गिरता है, वेस्ट भी होता है, लेकिन उसका पैसा किसान को देना पड़ता है। हम इस नैनो यूरिया की एक बोतल को पानी में मिलाकर एक बीघा में स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से उसकी एक-एक बूँद का उपयोग होगा। आज जो 10 लाख करोड़ रुपये हमने 5 साल में किसानों की खाद की सब्सिडी पर खर्च किया, आज जब हम इस नैनो यूरिया की रिसर्च से, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की हर क्षेत्र में चिन्ता रहती है, this will save around Rs.15,000 crore to Rs.20,000 crore on imports every year. आखिर यह देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। यह एक दूर-दृष्टि से ही सोचा जा सकता है।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नासा में हमारे परिणामों की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी चन्द्रयान मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है और शायद हम

उम्मीद करते हैं कि उसको सफ लौंडेंग भी होगी । निश्चयत तौर से होगी । लोकेन नासा का जो बजट है, क्या इसरो के पास उतना बजट है? वह विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ । मैं कह सकता हूँ कि नासा के पास जितना बड़ा बजट है, आज इसरो के पास उसके मुकाबले बहुत कम बजट है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक नासा के उतने बड़े बजट के बावजूद भी उनसे रिसर्च में आगे हैं । इसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने वैज्ञानिकों की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए । इसकी तारीफ तो हमें उसी दिन करनी चाहिए । इस बात को कौन देखता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसरो जाते हैं । प्रधानमंत्री जी स्वयं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं ।

महोदय, जिस तरह से प्रधान मंत्री जी इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हैं, यदि कोई बात भी हो जाती है, तो भी वे वैज्ञानिकों को हौसला देते हैं । कोविड की वैश्विक चुनौती में तमाम दुनिया के लोग लगे थे और कुछ अच्छी कंटीज को छोड़कर वैक्सीन नहीं बना पाए, लेकिन भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन यदि बना पाया है और कोविड का इतने अच्छे ढंग से मुकाबला कर पाया है, तो यह निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी की देन है क्योंकि प्रधान मंत्री जी स्वयं उन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों से मिलने गए तथा उनकी हौसला अफजाई की । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी सदन में आ गए हैं । मैंने फर्टिलाइजर का भी उल्लेख किया है और स्वास्थ्य का भी उल्लेख किया है । ये स्वयं भी मेहनत करते हैं, जिस तरह से नेनो यूरिया पर काम हुआ । इसरो की यदि बात करें तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सज हैं ।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । पिछले चार-छह वर्षों में हमारी सरकार ने किस-किस रिसर्च में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है । हम मानकर चलते हैं कि शोरगुल होगा, लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर उन्हें बुद्धि आ गई और वे चले गए । आज पूरा सदन और पूरा देश इस चर्चा को सुन रहा है । आज पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्प किया है, India made a massive jump in its ranking in the Global Innovation Index. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम दुनिया में 81वें रैंक पर थे ।

We were standing at 81st rank, वर्ष 2015 से वर्ष 2022 में हम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में 81वें रैंक से जम्प करके 40वें रैंक में पहुंच गए हैं । कल जब इस पर डिस्कशन करेंगे, पता नहीं हमें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए यह बात आज कह रहा हूँ कि सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं । वर्ष 2018 में भी इसी तरह से जुलाई महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, यहां

आविश्वास तो होगा नहीं, इसीलिए जब वर्ष 2018 में आविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो जनता ने भी देखा कि उसका जवाब सदस्यों ने अपने जनादेश से नहीं दिया, बल्कि जब वर्ष 2019 का चुनाव हुआ तो लोगों ने मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जीता कर भेजा। आज वर्ष 2023 में फिर जुलाई महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। History will repeat itself again. इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। वर्ष 2019 में स्पष्ट बहुत से हमारी सरकार बनी थी और अब वर्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसलिए वर्ष 2024 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और यूपी में 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें नम्बर पर हैं। India ranks second among thirty-four lower middle-income economies. क्या छह साल की इन्हें उपलब्धियां दिखाई नहीं दे रही हैं और इसलिए वे शोर कर रहे हैं? यदि वे चर्चा कर लें तो ये रिक्साइज करें या न करें, दुनिया भारत को इसलिए रिक्साइज कर रही है, हमारे प्रधान मंत्री जी को दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन छह सालों में भारत को उपलब्धियों का भारत देखा है, आत्मनिर्भर भारत देखा है और दुनिया की रैंकिंग में भारत को ऊपर आते देखा है। आप देखें कि हमने आर एंड डी पर कितना ग्रास एक्सपेंडिचर खर्च किया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूं कि the gross expenditure on R&D has increased more than three times in the last ten years. जब से हमारी सरकार आई, जो हम रिसर्च पर खर्च करते थे, उसे हमने तीन गुना बढ़ाया है। जहां कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को पांच किलो खाद्यान्न लगातार हमारी सरकार प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दे रही है, हमने कोविशील्ड का फ्री वैक्सीनेशन दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने रिसर्च पर भी तीन गुना खर्च बढ़ाया है, जिससे कि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें।

मान्यवर, मैं केवल प्वायंट की बात कर रहा हूं, मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। विमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूं। Womens participation in extramural Research and Development has also doubled in the last nine years. इसका मतलब हमने इस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में महिलाओं की संख्या को भी दोगुना किया है।

आज जिस तरह से इंडिया के रैंक्स हैं, India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world. मान्यवर, पूरी दुनिया की दीवारों पर इबारत लिखी जा चुकी है। पहले इंडिया में कौन इन्वेस्ट करता था? क्या पहले इंडिया में एफडीआई आता था? इंडिया से लोग बाहर चले जाते थे कि हम यूरोपीय देशों में जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे।? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं एकाध उपलब्धियों के बारे में बता दूँ, मैं कहीं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल उपलब्धियों का जिक्र कर दूँ ।

मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं ।

Now, India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transaction in the world. India R&D expenditure in PPP terms in total is 68 billion dollars which is sixth in the world. क्या यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम दुनिया में छठे नम्बर पर आ गए हैं । हम 68 बिलियन डॉलर्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं ।

माननीय सभापति : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, अभी यह कहा गया कि जब इस बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो राज्यों के लोगों ने कहा कि यह को-ऑपरेटिव फेडेरलिज्म के खिलाफ है । मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों में अभी तक रिसर्च पर क्या खर्च हो रहा है?

Overall, the State expenditure on R&D relative to GSDP is 0.08 per cent. राज्यों में रिसर्च के लिए पैसे नहीं है, केवल 0.08 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं ।

महोदय, पूरे ग्लोबल परिदृश्य में अभी आर एण्ड डी का करीब 60 प्रतिशत खर्च प्राइवेट सेक्टर में होता है और 35 प्रतिशत सरकार की तरफ से होता है । यू.एस.ए. में यह 70 प्रतिशत खर्च होता है । भारत में 65 प्रतिशत खर्च सरकार करती है और 35 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर करता है । यह सोचिए कि कितना असंतुलन है? हम दुनिया के ?एट-पार? नहीं हैं । आखिर इन सारी चीजों के बारे में कौन सोच रहा है? अगर इस राजनीति के पीछे कोई सोच रहा है तो वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सोच रहे हैं और वे दुनिया को आगे ले कर जाएंगे ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you Sir. Thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Bill namely, the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023.

I support and advocate the passage of the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023. It is a transformative and revolutionary legislation. It will save the future of scientific research and development in our nation. This ground-breaking initiative is designed to ensure equitable funding, foster private sector participation and facilitate collaboration

between academia and industry and this is all aimed at catapulting India to the forefront of global innovation and progress.

The primary objective of this Bill is to evolve colleges and universities in scientific research. It is disheartening to note that currently less than half of vast array of 40,000 higher learning institutions are actively engaged in research. This discrepancy indicates a pressing need to bridge the gap and instil a culture of scientific inquiry across the academic landscape by encouraging and supporting active researchers to take up NRF professorship and collaborate with existing faculty. The NRF will cultivate research capabilities within the universities and foster an ecosystem of innovation that will enrich our nation's intellectual capital.

One of the most commendable features of NRF is that it has an inclusive approach to research. It does not confine only to natural sciences rather it recognises the value of research in humanities, social sciences and arts.

This forward-looking integration is essential for nurturing creativity, critical thinking, and communication skills which are qualities that are indispensable for tackling complex societal challenges. Unfortunately, research in these domains has been historically underfunded and the NRF's establishment of dedicated Directorates for social sciences, Indian languages, and knowledge systems, arts, and humanities will provide the much-needed support and impetus for research in these spheres.

In addition to promoting a holistic approach to research, NRF is committed to identifying and prioritizing areas where science and technology interventions can contribute significantly to national objectives. From clean energy and climate change mitigation to sustainable infrastructure, improved transportation, accessible and affordable health care, NRF's focus on these priority areas is commendable. By aligning research efforts with our country's larger goals, NRF ensures that scientific advancements are strategically directed to uplift our society and contribute to national development.

However, we must acknowledge the existing challenges in our research ecosystem that demand immediate attention. The status of research and development in India is a cause of concern. Our country's spending on R&D currently stands at below 0.7 per cent of our GDP, a figure that falls short in comparison to many other under-developed nations. Even Egypt and Brazil allocate more substantial resources to R&D, and the gap between their investment and ours reflects the pressing need to bolster our research capabilities.

Moreover, the decline in gross expenditure on R&D over decades serves as a stark reminder of the urgency in revitalizing our research sector. This decline signifies a slowdown in research progress which is detrimental to our nation's growth and development. Further, eminent institutions like the IITs and IISc get a bulk of research funding but the State Universities get very little funding. This is a point of great concern. NRF's emphasis on increasing funding from both Government and private sources is a step in the right direction.

We also laud NRF's ambition and potential. It is crucial to acknowledge the challenges that lie ahead. The financial crunch faced by NRF is a matter of concern. While the inclusion of private sector in funding is an encouraging development, we must carefully consider the strategy for raising the necessary funding amounting to Rs. 50,000 crore for five years.

Functional autonomy is also a crucial aspect which needs to be addressed. Timely disbursement of funds is vital for researchers to embark on their projects without unnecessary delays.

The NRF Bill, 2023 is a momentous opportunity to revolutionise scientific research in India. By ensuring equitable funding, prioritizing national objectives, and fostering collaboration, NRF will unleash the full potential of our researchers and innovators. More so, women and people belonging to SCs, STs, OBCs and minorities should be encouraged. Equal growth has to be ensured in towns and tier 3 State Universities. Thank you, Sir.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ? राजेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथी मेज थपथपा रहे हैं। रिसर्च चाहे किसी भी चीज़ पर हो, पिछले दिनों गन्ने पर जो रिसर्च की गई, उससे गन्ने के पौधों की हाइट बढ़ी। उससे जो सॉलिड गन्ना पैदा हुआ, जिसने पूरे देश में इतनी ज्यादा चीनी पैदा हुई कि विदेश के पैमाने पर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के सारे लोगों में उथल-पुथल मची और व्यावहारिक तौर पर उन्होंने विरोध किया। कानूनी तौर पर वे लोग इंटरनेशनल कोर्ट में गए, जहां पर वे केस जीते और हम हारे। हमने हार में भी जीत ढूंढी है। इथेनाल पर रिसर्च करने के बाद, हमने पूरे देश में इथेनाल की जो पैदावार की है, उसकी पूरी तरह से कंजम्प्शनन हुई है। इसकी तरफ देश ने एक अच्छी शुरुआत की है, इसलिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी मेज थपथपा रहे थे। यह किसानों के लिए अच्छी बात है।

महोदय, मैं कहूंगा कि जहां देश को इतना फायदा हो रहा है और इकोनॉमी में इस चीज से इतनी मजबूती आई है तो हमारे किसानों को भी कुछ न कुछ सुविधा दी जाए। इससे हमारे किसानों को लगेगा कि हम भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि विश्व में हमारी जो चौथी और पाँचवी आर्थिक स्थिति है, वह तीसरे नंबर की तरफ चले। यह फाइव ट्रिलियन डॉलर की तरफ चले। इसकी मैं मांग करता हूँ।

दूसरा, पूरे देश में आज की तारीख में हर चीज पर रिसर्च होनी चाहिए और इसके लिए बजट भी बढ़ना चाहिए, खासकर जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, अमरोहा और गौतमबुद्ध नगर लोक सभा क्षेत्र है, यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है। इन क्षेत्रों के किसानों की आय डबल की बजाय तीन गुना कैसे हो, इसके लिए मेरठ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह काफी मजेदार बात है। हमारे सामने सरकार और बीजेपी के जो साथी बैठे हैं, वे काफी अच्छा माहौल बनाते हैं। इन्होंने कांग्रेस वाले का पता साफ कर दिया। अभी ये सारे लोग भागे हुए हैं, मैदान खाली पड़ा हुआ है। अभी आप जो चाहें, करते रहें, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथी जगदम्बिका पाल जी जरा ध्यान दें। जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि हमारी 80 की 80 सीटें आएंगी। हमारा साढ़े 13 परसेंट वोट लठ सा खड़ा है। अगर आपका साथ मिल गया तो 80 सीटें यहां भी और 50 सीटें बाहर भी मिलेंगी। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाण, महाराष्ट्र में कहीं पर 9 परसेंट, 7 परसेंट, 4 परसेंट, 3 परसेंट, 2.5 परसेंट हमारा वोट है। अगर आपने नजदीक नहीं लाया और हम दूसरी तरफ चले गए तो यू.पी. में ही 60 सीटें और बाहर 50 सीटें कम हो जाएंगी। पहले दिन ही बढ़िया लड़ाई हो जाएगी। कुमारी बहन मायावती कह चुकी हैं कि हम चारों प्रदेशों में अलग लड़ेंगे या चारों प्रदेशों में बाद में समझौता करेंगे। अगर 80 सीटों की बात करनी है तो आप ठीक-ठाक बात कर लीजिए।

महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान केंद्र की मांग करता हूँ। हमारे किसानों सहित दूसरी चीजों पर इतना ज्यादा रिसर्च हो कि उनकी आय दोगुनी की

बजाय तीन गुनों हो जाए ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I want to bring to the notice of the hon. Minister that we must have a Railway Engineering University. China has built its railroads right up to Ladakh and LAC. It is necessary to do research on railway engines, wagons, and carriages.

They should be light in weight. The railway engines operating at 14,000 feet will need special fuel. So, it is my proposal that if in South America, the railways can operate at 14,000 feet above sea level, surely, we can build our railroads up to the border with China. That is my humble request.

The Himalayas are the youngest mountains in the world. When we tunnel them, they tend to break. It is very necessary to have a new technology to tunnel these mountains and make light bridges, light carriages, and light wagons. The armed forces in the North-East, Ladakh and Kashmir should be fully equipped with provision of army wear and other things. That is my humble request. Let me thank the Government for passing an order to renovate the railway stations in Punjab. Thank you very much.

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक को हम लोग पारित कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के साथ-साथ, मैं आईआईटी दिल्ली का भी एक ग्रेजुएट हूँ । इंजीनियर होने के नाते, जो इस क्रांतिकारी बिल को आज पारित कर रहे हैं, पूरी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ । आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज अपने चन्द्रयान रॉकेट के द्वारा लूनर आर्बिट में हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर इस रॉकेट को ले आए हैं और आज उनको इस विधेयक के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा । हम लोग न सिर्फ चन्द्रमा तक पहुंचेंगे, हम लोग मार्स भी पहुंचेंगे और सोलर सिस्टम को भी हम लोग पार करेंगे । यह आज हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है । सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है और मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि हमारे विपक्ष के साथी यहां पर ये सब बातें सुनने के लिए नहीं हैं । ?(व्यवधान)

रितेश जी हैं, लेकिन और तो कोई नहीं है । चलिए, आप ही हैं, आप जरूर उसका सबके सामने प्रचार करिएगा । माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण अर्थव्यवस्था में हम आज दसवें नंबर से पांचवें नंबर पर आए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में, जहां हम लोगों को प्रचंड बहुमत की सरकार फिर मिलने वाली है, कि हम लोग तीसरे नंबर पर आएंगे । हम लोग यहां ऐसे बहुत कम कानून पारित करते हैं जिसको पारित करके हमें विश्वास होने लग जाता है कि सिर्फ तीन नंबर पर नहीं, एकदम टॉप पर हमारी अर्थव्यवस्था आएगी । अगर इक्कीसवीं सदी किसी की भी सदी है, तो वह साइंस और इंजीनियरिंग की सदी है । इस बिल के द्वारा हम लोग साइंटिफिक और

इंजीनियरिंग रिसर्च जो कांटिंग एज पर करेंगे, उसके द्वारा हम लोग एक बहुत क्रांतिकारी कदम और बहुत ठोस कदम उठाने वाले हैं । It is well known that a lot of scientific and engineering prowess of the United States of America is due to the National Science Foundation where post-World War-II, through peer reviewed grants, they have built up capabilities in many different scientific disciplines. What the hon. Prime Minister has done through the National Research Foundation is that he enables India to establish the same kind of capabilities in many, many important scientific and engineering disciplines including artificial intelligence. Hon. Minister saheb talked about quantum computing. We have a quantum mission underway. We are doing very, very sophisticated research in green hydrogen as Jagadambika Pal ji has said. We are going to be taking very major steps in semi-conductors and very importantly in space research as well through the establishment of the National Research Foundation.

There are three or four aspects to this that, I think, are very important for hon. Members to realise. Number one is that this will be staffed with best experts and the best scientists in the world whether they may be from India or around the world through an independent expert body that will establish directorates for these disciplines and ensure that we spread the funds widely across our country to do appropriate targeted research. Here, I want to add one point, which is a very important point for the hon. Members to consider. It is not only to the IITs ? of course, I am a proud graduate and the IITs are doing cutting edge scientific and engineering work in many disciplines ? but also to other universities and research institutions across India, these peer reviewed competitive grants will be provided so that we build capacity, capability, and world-class expertise across India.

I dare say, I proudly say that in my own Hazaribag where we have the largest University in Jharkhand, the Vinoba Bhave University, we are doing exemplary research in mining, geology and tribal studies and I will very much hope because we are including humanities also where we can do scientific and sociological research through these kinds of grants or experts, that even the Vinoba Bhave University will benefit greatly. All the universities and institutes in your constituencies will also benefit greatly

from the kind of grant-making and the kind of expertise that we will be building through the National Research Foundation.

It is indeed a historic Bill and I am really, really sad, as the hon. Minister said, that our Members of the Opposition are not here to be able to appreciate it and understand how important and how game-changing this is for India and India's economy and scientific and engineering community. Our start-up eco-system will benefit. Where does the innovation come from? That power is our start-ups, if we have to build world beating companies like Google, Apple, and Meta. They have come out of Stanford University. They have come out of the University of California, Berkeley. They have come out of MIT. They have come out of Caltech. They have come out of Harvard University. Unless we provide that type of support and encouragement to our research institutes and to our universities, we will not beat these world-leading companies. We will not create our own world-leading industries and that will hurt our job creation and our competitiveness in the long run.

So, this Bill is vitally important for our human development, for our universities, and for the growth of new industries in India as well.

The second point I want to emphasise on is this. I must commend the hon. Minister and all the experts who have worked on this. The design of the National Research Foundation, which is going to bring experts from around the world, which is going to be independent, which is going to have these different directorates, has been done very, very thoughtfully. Here, I must point out that the funding for this, as the hon. Minister said, is going to come from multiple sources. So far, most of our science and engineering has only received funding from the Government. As Jagdambika Palji said, a lot of it in the State Governments has been very, very modest. But here, not only are we going to mobilize the resources of the national Government but we are also going to mobilize the resources of the corporate sector, philanthropists, and institutions around the world. All of that can be collected through the National Research Foundation and then, provided to a diverse set of institutions across India. This is a revolution in the making.

We have to understand how important this Bill is. I want everyone to recognise what the hon. Prime Minister and the hon. Minister have done through this. It is to really transform India's engineering and scientific research. ?(Interruptions) That is why, I stand in support of this Bill. I wish, my colleagues from the Opposition were here as well. ?

(Interruptions) आज हम लोग क्रांतिकारी कदम ले रहे हैं, इस क्रांतिकारी कदम से हम भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के इतिहास का कायाकल्प कर रहे हैं। आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें। माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Hon. Chairperson Sir, I am representing the Opposition. ?(Interruptions)

माननीय सभापति : हां, ठीक है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने न केवल इस बिल का समर्थन किया, बल्कि हमारा उत्साहवर्धन भी किया। माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ नेता हैं। जाहिर है, जो सीनियर नेता होते हैं, उन्हें इस बात का खेद भी होता है कि विपक्ष के लोग इस अवसर से अपने आपको वंचित कर रहे हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। जब वह यह बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि बाहर जाकर 2028 के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक सुचारू तरीके से अपनी बात रखी है, उसका स्वागत है और उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है।

डॉ. टी रंगैया जी ने इक्विटेबल फंडिंग की बात रखी। इस बात का भी उल्लेख किया कि यह लैंग्वेज न्यूट्रल रहेगा। माननीय सदस्य इस बात की दाद देंगे कि इसी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विज्ञान की भाषा का दूसरी भारतीय भाषाओं में भी शिक्षण-प्रशिक्षण हो, इसकी व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हिन्दी में कैरिकुलम प्रारंभ हो चुके हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि आगे चलकर आठवीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं, उसमें भी हम so that we are able to provide democratisation and language-neutral curriculum to all the youth and students. श्री मलूक नागर साहब गन्ने की बात करके चले गए। नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन में यदि गन्ने को लेकर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर उतना ही कन्सीडर किया जाएगा जितना दूसरे विषयों पर किया जाएगा। यकीनन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्गेनिक खेती में बहुत सारा काम हो रहा है और आप उसमें माहिर हैं। सरदार सिमरन जीत सिंह मान साहब ने रेलवे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं इस समय इस विषय पर

बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मंत्रालय से उसका सीधा-सीधा संबंध नहीं है ।

महोदय, जयंत सिन्हा का जिस प्रकार का अध्ययन रहा है, उन्होंने इस बिल के मूल भाव को समझकर अपने अनुभव से विचार रखे हैं । यदि इस प्रकार का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि हमने जिस प्रकार की कल्पना की है, उस ढंग से हम इस बिल को लागू करने में सफल रहेंगे ।

महोदय, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए कुल मिलाकर इस चर्चा को समेटते हुए कहूंगा कि पिछले आठ-नौ वर्षों में भारत अच्छे स्तर पहुंचा है, यह केवल मैं नहीं कह रहा, यहां बैठे हुए साथी भी कह रहे हैं । हम यह इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी या किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं । यह भौगोलिक मापदंड है जिसने भारत को मान्यता दी है । ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, लेकिन विश्व में इसकी मान्यता है । हम वर्ष 2014 से पहले 81वें नंबर पर थे, 40 नंबर का जम्प हुआ है, अब हम 42 नंबर पर हैं और दुनिया इस बात को मानती है ।

महोदय, वर्ष 2014 से पहले देश में स्टार्टअप ईको सिस्टम में 350-400 स्टार्टअप्स थे । माननीय मोदी जी ने लालकिले से आह्वान किया ? ? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया? और देखते ही देखते अब एक लाख की संख्या पार हो गई है । विश्व के मापदंड पर स्टार्टअप में हम तीसरे दर्जे पर हैं । बायोटेक के स्टार्टअप मात्र 50 थे और अब बढ़कर 6000 हो गए हैं । वैक्सीन की भी हमारी सक्सेस स्टोरी है । वह देश, जिसे देखकर सारा विश्व कतराता था कि 130-140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अगर कोविड फैल गया तो इनको अपना तो रख-रखाव करना नहीं आता और ये हमें भी ले डूबेंगे । इस देश ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि हमने दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपहार के रूप में दी । जयंत जी ने चंद्रयान की कथा सुनाई कि यह घूमता-घूमता चन्द्रमा के नजदीक आ रहा है । यह पहले बड़ा ऑर्बिट फिर छोटा ऑर्बिट तय करेगा और 23 या 24 तारीख के आसपास लैंड करेगा । भारतवासी इसे जितनी उत्सुकता से देख रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता से अमरीकन लोग भी देख रहे हैं कि न मालूम वहां से क्या प्रमाण मिलेंगे, क्या इनपुट्स मिलेंगे । हमारी क्षमता की इस तरह की मान्यता हो चुकी है । यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि माननीय मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया कि हम साइलोज़ से बाहर निकले । वैक्सीन की कथा में सम्पूर्ण भारत सरकार का कन्सेप्ट है । इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का योगदान रहा, विज्ञान मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने भी योगदान किया । मार्केटिंग के लिए कॉमर्स मंत्रालय आया, विदेश मंत्रालय भी आया । वैक्सीन मैत्री का अभियान भी शुरू किया

गया । इस प्रकार से इंटीग्रेटेड एप्रोच और साथ ही साथ एक्सटेंडेड इंटीग्रेशन के माध्यम से, न केवल सरकार के विभागों तक सीमित न रहकर समाज के दूसरे वर्गों, भले ही इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो या उद्योग जगत हो, साथ लेकर चलें ताकि अगले 25 वर्षों के अमृत काल को उस रूप में ढाल सकें, जिसकी हमने कल्पना की है । This Bill spells out democratisation of human resource as well as democratisation of funding. जैसे रंगैया जी ने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा और जगदम्बिका पाल जी ने भी इशारा किया । जो लोग दुहाई देते हैं कि प्रदेशों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं होता, शायद उन्हें यह बात मालूम ही नहीं है, उनको अनुमान ही नहीं है कि उनके अपने नियंत्रण में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहां मात्र दस प्रतिशत रिसर्च के लिए फंडिंग दी जाती थी । फंडिंग स्पर्द्धा के आधार पर दी जाती थी और स्पर्द्धा में बड़े संस्थान आगे बढ़ जाते हैं । मैं यह बात साझा करना चाहता हूं कि There will be competition of State universities within State universities, excluding IITs and other institutions ताकि उनके लिए निर्धारित की गई राशि उन तक ही रहे और वे धीरे-धीरे अपना स्तर बढ़ा सकें । ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों की अधिकतर संख्या इन्हीं विश्वविद्यालयों में रहती है । दूसरी बड़ी उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में और कुल मिलाकर दूसरे क्षेत्रों में रही है ।

16.00 hrs

उसको जगदम्बिका जी ने एक इशारे में कहा कि ?Today, the world looks up to us with seriousness.? क्या पहले कभी किसी ने सोचा था कि हमारे यहां से क्लाइमेट की बात होगी, क्लीन एनर्जी की बात होगी? वे तो समझते थे कि ये सांप-सपेरो की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज इनके दिमाग के ऊपर से उड़ जाता है । आज प्रधान मंत्री जी ने काँप की मीटिंग में साहस करके यह बात कही कि सन् 2070 तक we will be net-zero. That is, we have taken a lead in the global issues which earlier were believed to be the exclusive domain of some of the so-called developed countries. आज हम भी उसी स्तर पर हैं । हम उनको लीड दे रहे हैं और वे हमें देख रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में कोई संदेह नहीं कि जितनी भी प्रगति होगी, जितना विकास होगा तथा अर्थव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी That will be entirely technology-driven. सभापति महोदय, इतनी तीव्र गति से इस समय टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि रात को हम जो सोचकर सोते हैं कि सुबह यह होगा, वह रात तक हो गया होता है । उस दिन मैंने सोचा कि 31 तारीख को चंद्रयान सुबह आर्बिट से निकलकर दूसरी तरफ जाएगा, तो मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे थे । रात को 12 बजे जैसे ही मैं सोया, साढ़े 12 बजे वह चला गया । जब मैं उठा, तो पता चला कि 4 घंटे पहले ही वह जा चुका था । इतनी तेज गति से टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है । Not

only the technology is constantly moving forward but the pace is also increasing. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की आगे चलकर चुनौती रहेगी, the optimum synergy between artificial intelligence and human intelligence. भारत ने जो कल्पना की है, जिसका जिक्र मोदी जी अक्सर करते हैं यानी ?2047 का भारत-शताब्दी भारत? । भारत अपनी आजादी की जब सौवीं सालगिरह मनाएगा, तो उस शिखर पर पहुंचने के लिए और अपनी मान्यता कायम करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा । Our parameters have to be global. Our challenges have to be global. Our strategies have to be global. And our competitiveness has to be global. उसके लिए जैसा कि जयंत जी ने कहा कि अमेरिका की नैशनल रिसर्च सोसायटी आज हमसे पूछ रही है कि आपने नैशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या-क्या ड्राफ्ट किया? मुझे विश्वास है कि अगर हम इसे उस तरह से जमीन पर उतारने में कामयाब हुए, तो हमारी संस्था भी दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक तरह का रोल मॉडल रहेगी । महोदय, बहुत बात न करते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि This is going to be an arrangement which will enable democratic pooling of scientific resources. जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी प्रतिभा इनवेस्ट करने के मौके नहीं थे । हमने इसमें यह भी प्रावधान किया कि हमारे जो एनआरआई युवा बाहर चले गए हैं, उनको भी वापस लाया जा सके । चूंकि उनको यहां अवसर नहीं मिलता था, इसलिए वे बाहर जाते थे । इसमें उस चीज का भी ध्यान रखा गया है । साथ ही साथ democratisation of the funding में हमारे पास ऐसी युवा प्रतिभाएं हैं, we have young brains who are ready to put in their talent, and we also have the industry which is ready to invest. But we were constraining ourselves because of self-made barriers. आज मोदी जी ने हमें उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है, ताकि हम खुली हवा में, खुली फिजा में तेज गति से 25 साल आगे बढ़ सकें । नैशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल केवल साइंस, नवाचार तक ही सीमित नहीं रहेगा । यह आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा । अतः मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व के साथ इस बिल का अनुमोदन करना चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey, do you want to make a brief intervention? If so, kindly make it very brief.

*m09श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर, मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बिल सामने आया है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ब्लॉक चेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, जिसके ऊपर सरकार की एक नकारात्मक सोच रहती है कि इससे हो सकता है कि अवाम

को बहुत नुकसान हो सकता है। अन्य देशों में देखा जाता है कि उनको एक साइलेंस में रखकर उन पर अनुसंधान होता है। क्या यह होगा?

दूसरा, जो 50 हजार करोड़ रुपये की आप बात कर रहे हैं, उसमें 35 हजार करोड़ रुपये अन्य जगहों से आएगा, इस संबंध में ठोस जवाब क्या है? एक हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे पास 35 हजार करोड़ रुपये आ जाएगा। इस पर कोई ठोस जवाब दें कि यह पैसा कहां से आएगा? धन्यवाद।

*m10डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह बिल इस प्रकार का है कि इसको समझना आवश्यक है। इसलिए, मैंने सभापति महोदय से अनुमति ली है, वरना यह बिल दो मिनट में पास किया जा सकता है। मैं दो-तीन मिनट लूंगा, क्योंकि उन्होंने एक विषय रखा है, जो शायद समझने के लायक है। आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। आपके प्रश्न में ही उत्तर था। पहले जो ब्लॉकचेन और क्रांटम को लेकर बाधाएं थीं, उससे मुक्ति प्राप्त करने का ही यह प्रोसेस है। इसके लिए इस दिशा में काम पहले से ही आरंभ हो चुका था। जैसे unlocking of the space sector हुआ और जियो स्पेशल पॉलिसी हुई, क्या कभी इसके बारे में किसी ने सोचा था। श्रीहरिकोटा से जिस दिन चंद्रयान को लांचिंग हुई, उस दिन पत्रकार आकर मुझसे पूछने लगे कि साहब पहले और अब में क्या फर्क पड़ा है? कांग्रेस वालों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसे ही ढोल बजा रहे हैं। आज क्या फर्क पड़ा है? मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप यहां पहले कभी आए थे? तो उन्होंने कहा नहीं। एक हजार मीडिया के मित्र वहां स्थान पर खड़े थे, क्योंकि वह फाटक आज तक बंद था। श्रीहरिकोटा का वह फाटक मोदी जी ने खोला है। We are already into that direction.

दूसरा, जैसे आपने कहा कि वह 36 हजार करोड़ रुपये हैं, जो बाहर से आएगा। वह देखने में फिगर लगता है कि कैसे आएगा। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो ये 36 हजार करोड़ रुपये पाँच साल के लिए हैं। एक साल के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपये हैं। अब 7 हजार करोड़ रुपये में से हमारे पास इनोवेशन फंडिंग हुआ करती है। मैं इसको बड़ी बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत फिजिबल है और यह उससे ज्यादा आएगा। (व्यवधान) हमें सिर्फ 7 हजार करोड़ रुपये रेज करने हैं और वह रेज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले ही वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो सीएसआर होता है, उसमें आर एंड डी भी शामिल कर लिया गया है। यदि कोई 10 प्रतिशत भी आर एंड डी में देता है तो दो-तीन हजार करोड़ रुपये तो वही दे देगा। अगर उसको यह संकोच रहे कि मैं दो-तीन हजार करोड़ रुपये दूंगा तो वह वापस नहीं आएगा, तो मैं उसको कहूंगा इनोवेशन फंड से मैं भी दो-तीन हजार करोड़ रुपये देता हूँ। हम इकल पीपीपी

मॉडल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी तो 14 हजार करोड़ रुपये हैं। उसमें से 10वें आप उसको तकसीम कीजिए। 10,000 करोड़ रुपये प्लस 4,000 करोड़ रुपये, जब हम 14,000 करोड़ रुपये का दस बार करेंगे तो उतना मेरे पास भी है, लगभग 150-200 हजार करोड़ रुपये होंगे। जब मैं बराबर की फंडिंग करूंगा तो एक पीपीपी मॉडल डेवलप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको थोड़ा-सा स्टैटेजाइज करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि मानो 36,000 करोड़ रुपये कहां से आएं, जैसे किसी को 36,000 करोड़ रुपये वहां पर सहयोग करने हैं तो ऐसा नहीं है। यह एक बड़ा बिजनेस मॉडल बनेगा। निश्चय ही हम इसमें सबका सुझाव लेंगे। आप जैसे मित्रों ने, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है। आपके इनपुट्स भी समय-समय पर स्वागतयोग्य होंगे।

*माननीय सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न यह है:

?कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन ? उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने ही अपने संशोधन दिए हैं। लेकिन, अभी वे इस सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अतः मैं इस विधेयक के सभी खंडों को सभा के नेणय के लिए एक साथ रख रहा हूँ ।

?कि खंड 3 से 27 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed?.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
